



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2011/माघ 21, 1932

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2011/MAGHA 21, 1932

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2011

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : यूएसए तथा चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फेनॉल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/01/2011-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटिवस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीनी ताइपेई (जिसे एतदपश्चात् "संबद्ध देश" कहा गया है), यूएसए तथा कोरिया गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फेनॉल (जिसे एतदपश्चात् "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए 7 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

2. और यतः संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 3 मार्च, 2008 को सी.शु. अधिसूचना सं. 30/2008-सी.शु. के तहत लगाया गया था।

3. और यतः प्राधिकारी को मध्यावधि समीक्षा हेतु मै. फार्मोसा कैमिकल एंड फाइबर कार्पोरेशन जो चीनी ताइपेई का फेनॉल का निर्यातक है और मै. सेंचुरी प्लाइ बोर्ड्स (आई) जो फिनॉल का आयातक है, से पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए मध्यावधि समीक्षा हेतु दो याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच की भाँति और वर्तमान समीक्षा आवेदन में भी विचाराधीन उत्पाद फिनॉल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

“ विचाराधीन उत्पाद यूएसए, कोरिय गण., ताइवान के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित फिनॉल है। फिनॉल मूलभूत कार्बनिक रसायन है जो सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। उत्पाद का विपणन दो रूपों-बल्क और डिब्बाबंद रूप में किया जाता है। बल्क बिक्री सामान्यतः खुले रूप में की जाती है जबकि डिब्बाबंद परेषण अत्यंत कम कंटेनर भार में हो सकते हैं और इन्हें सामान्यतः ड्रमों में रखा जाता है। फेनॉल का उपयोग फेनॉल फॉर्मलिड्हाइड रेजिनों, लेमिनेट्स, प्लाइवुड, प्लास्टिक बोर्ड, बिस्फेनॉल-ए, अल्कायल फेनॉल, भेषज, डाइ-फेनॉल ऑक्साइड आदि में किया जाता है। यह उत्पाद भारतीय वर्गीकरण के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 तथा 2707.99 के अंतर्गत वर्गीकृत है। ”

तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

समीक्षा के आधार

5. मै. फार्मसा कैमिकल एंड फाइबर कॉर्पोरेशन (एफसीएफसी), चीनी ताइपेई तथा फेनॉल के एक आयातक मै. सेंचुरी प्लाइबोर्ड्स (आई) लि. ने परिवर्तित परिस्थिगत समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार बताएँ हैं :

(क) मूल जाँच की तुलना में प्रस्तावित जाँच अवधि के दौरान मूल कच्ची सामग्री बेंजीन/प्रोपीलीन की कीमतों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ख) चीनी ताइपेई और यूएसए से हुए निर्यातों के संबंध में मूल जाँच की तुलना में भारत के लिए संबद्ध सामग्री की निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रस्तावित जाँच अवधि के दौरान आवेदक निर्यातक (एफसीएफसी) द्वारा न्यूनतम पाठन मार्जिन का दावा किया गया है।

(घ) भारत में घरेलू बिक्री के बारे में भी यह दावा किया गया है कि उसमें मूल जाँच की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योगों के निष्पादन में मूल जाँच के बाद बेहतरी हेतु भारी परिवर्तन हुआ है। आगे यह दावा किया गया है कि यूएसए और चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण क्षति मार्जिन नकारात्मक हो गया है।

परिस्थितियों में हुए इस परिवर्तन को पर्याप्त और मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत हेतु उचित माना गया है।

शामिल देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीनी ताइपेई और यूएसए हैं।

जांच की शुरूआत

7. लागू उपाय की समीक्षा की आवश्यकता बताते हुए परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदकों द्वारा प्रदत्त सकारात्मक सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ़ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के उपबंध के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा उचित है।

दिनांक 7 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/5/2005-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा इस बात की जांच करने के लिए कि क्या चीनी ताइपेई और यूएसए के मूल के या वहाँ से निर्यातित फेनॉल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखना पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या शुल्क को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने या दोनों ही स्थितियों में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, नियमों के अनुसार जांच शुरू करते हैं।

प्रक्रिया

8. इस जांच से यह निर्धारित होगा कि क्या शुल्क को निरंतर लागू रखना पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या शुल्क को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने या दोनों ही स्थितियों में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- क) जहाँ तक यूएसए और चीनी ताइपेई का संबंध है, इस समीक्षा में 7 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।
- ख) इस जांच में शामिल देश चीनी ताइपेई और यूएसए हैं।
- ग) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

जांच अवधि

9. इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक की अवधि। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

10. भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार/प्रतिनिधियों, आयातकों तथ प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा सं. 216-सी,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से इस जाँच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

समय सीमा

12. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय सारांश

13. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई किसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार्य होगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इन्कार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 10th February, 2011
(Mid Term Review)

Subject : Initiation of Mid Term Review of the anti-dumping duty imposed on imports of Phenol originating in or exported from USA and Chinese Taipei.

No. 15/01/2011-DGAD.— Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as 'AD Rules'), vide Notification No. 14/5/2006-DGAD dated 7th January, 2008, the Designated Authority (herein after referred to as 'the Authority') notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Phenol (hereinafter referred to as 'subject goods') originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as 'subject country') USA and Korea RP

2. And WHEREAS definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No: 30/2008-Customs dated 3rd March, 2008.

3. And WHEREAS two petitions for Mid Term Review has been received by the Authority from M/s Formosa Chemical & Fibre Corporation, an exporter of Phenol from Chinese Taipei and M/s Century Plyboards (I) Ltd., an importer of Phenol, substantiating the need for Mid Term Review of the anti dumping duty earlier imposed.

Product under Consideration

4. The Product under Consideration, as in the original investigation and also in the present review application is Phenol. As per the original investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under

"The product under consideration is Phenol originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms – bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols,

508 96/11-2

Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.99 as per Indian Trade Classification.

However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Grounds for Review

5. M/s Formosa Chemical & Fibre Corporation (FCFC), Chinese Taipei and M/s Century Plyboards (I) Ltd., an importer of Phenol have listed the following grounds for changed circumstances review :

- a) Basic Raw Material Benzene/ Propylene prices have shown an increase during the proposed period of investigation as compared to the original investigation.
- b) There is an increase in export price of subject material to India as compared to the original investigation in respect of exports from Chinese Taipei and USA.
- c) De minimus Dumping Margin has been claimed by the applicant exporter (FCFC) during the proposed period of investigation.
- d) Domestic sales price in India has also been claimed to have shown significant increase as compared to the original investigation. It has been claimed that domestic industries performance has changed significantly for the better since the original investigations. It has further been claimed that injury margin on account of subject goods import from USA and Chinese Taipei have become negative.

This change in circumstances has been considered significant and appropriate to initiate a midterm review.

Country (ies) Involved

6. The countries involved in the present investigation are Chinese Taipei and USA.

Initiation

7. Having regard to the positive information provided by the applicants indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of section 9A(5) of the Customs tariff (Amendment) Act 1995 as amended read with Rule 23 of the Anti dumping rules.

Having decided to review the Final Findings notified vide Notification No.- 14/5/2006-DGAD dated 7thJanuary,2008, the Authority hereby initiates the investigations in terms

of the Rules, to review whether continued imposition of the anti dumping duties on imports of Phenol originating in or exported from the Chinese Taipei and USA is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both.

Procedure

8. The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- a) The review will cover all aspects of Notification No 14/5/2006-DGAD dated 7th January 2008 in so far as they pertain to USA and Chinese Taipei.
- b) The countries involved in this investigation are Chinese Taipei and USA.
- c) Provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Anti-Dumping Rules supra shall be *mutatis mutandis* applied in this review.

Period of Investigation

9.. The period of investigation (POI) for the purpose of this review will be 1st January 2010 to 31st December 2010. However, injury analysis shall cover the years from 2007-08, 2008-09, 2009-10 and POI.

Submission of Information

10.The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the Domestic Industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 216-C, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

12. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned hereinabove not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

Non-confidential summary

13. All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2), which will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2) of the AD Rules.

Inspection of Public File

14. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority